nwda.gov.in

'नया पानी' की अवधारणा पर करना होगा काम : प्रो. अरुण कंसल

जागरण विमर्श जल संरक्षण को प्रभावी कैसे बनाएं?

सुधीर कुमार ● जागरण

2100 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिल्ली में आता है, अधिकतर बह जाता है

1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी की उपलब्धता होने पर संकट आ सकता है

- पार्कों में छोटे-छोटे जलाशय बनाए जाएं
- मोहल्ला स्तर पर एसटीपी प्लांट लगाकर इस्तेमाल करना होगा

प्रो. अरुण कंसल ● जागरण

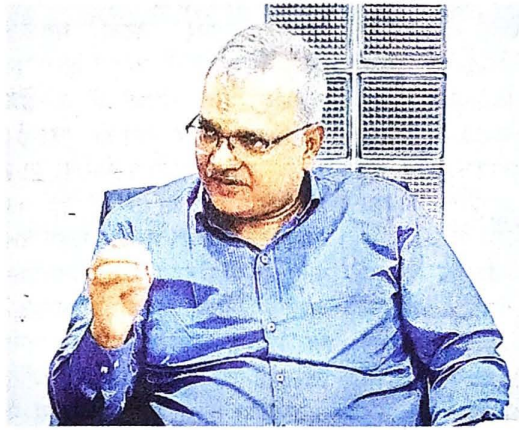

घरेलू उपकरणों से घटा पानी का खर्च

प्रो. कंसल ने कहा कि इलेक्ट्रानिक घरेलू उपकरणों वाशिंग मशीन और डिश वाशर की वजह से पानी का खर्च घटा है। वाशिंग मशीन से एक साथ कई लोगों के कपड़े धुल जाते हैं, जिससे पानी खर्च में कमी आई है। हालांकि शावर का उपयोग करने से पानी अधिक खर्च होता है।

जल गुणवत्ता सूचकांक जारी करना शुरू करें एजेंसियां

एनसीआर में लोगों की आरओ पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जबकि 80 प्रतिशत जगहों पर आरओ की जरूरत ही नहीं है। जहां सरफेस वाटर यानी नदियों का पानी पहुंच रहा है, वहां तो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ग्राउंड वाटर की स्थिति में आरओ की जरूरत हो सकती है। यहां यह भी देखने की जरूरत है कि टीडीएस अगर नमक की वजह से ज्यादा है तो नुकसान्देह नहीं है। कई जगहों पर सिर्फ यूवी रेडिएशन बेस्ड फिल्टर से काम चल सकता है। आरओ से बहुत पानी बर्बाद होता है। आरओ पर निर्भरता बढ़ने की वजह जल बोर्ड पर लोगों का विश्वास कम होना है। एजेंसियों को चाहिए कि वह नियमित रूप से जल गुणवत्ता सूचकांक जारी करे।

नोएडा: अभी एनसीआर के लोग जल संकट को झेल रहे हैं। लेकिन आपात स्थिति नहीं है। अगर हम अभी सचेत नहीं हुए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। जल संरक्षण के लिए हमें अब पारंपरिक तरीके के साथ ही 'नया पानी' की अवधारणा पर काम करना होगा। एसटीपी के विकेंद्रीकरण पर फोकस करना होगा। वर्षा जल संचयन के पुराने तरीके में भी बदलाव लाना होगा। किसी उत्पाद को बनाने में कितना जल दोहन हो रहा है, इसके लिए वाटर फुट प्रिंट जारी किया जाना चाहिए। जल संकट को दूर करने के लिए अगले पांच साल की जरूरत को ध्यान में रखकर योजना बनाने की जरूरत है। एजेंसियों को जल गुणवत्ता सूचकांक जारी करना चाहिए। यह कहना है आइपीसीए- सेंटर फार वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसर्च के केंद्र निदेशक प्रोफेसर अरुण कंसल का। यह संगठन टेरी के साथ मिलकर काम करता है। वह सोमवार को दैनिक जागरण नोएडा कार्यालय में साप्ताहिक विमर्श कार्यक्रम में पहुंचे थे।

प्रो. कंसल ने कहा कि हम सीधे तौर पर जितने पानी का उपयोग करते हैं उसकी तुलना में परोक्ष रूप से अधिक पानी का दोहन करते हैं। जैसे एक किलो चावल के उत्पादन में दो हजार लीटर पानी का दोहन होता है। देश में जल की उपलब्धता 2100 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति है, आजादी के समय यह उपलब्धता 5100 क्यूबिक मीटर थी। संकट की स्थिति 1700 क्यूबिक मीटर से कम होने पर है। हालांकि पानी का वितरण देश के सभी हिस्सों में एक समान नहीं है, कुछ हिस्सों में यह उपलब्धता 20 हजार क्यूबिक मीटर तक है तो कुछ इलाकों में 400 मीटर ही है।

उन्होंने कहा कि जहां तक दिल्ली की बात है तो यहां कृषि क्षेत्र कम होने से पांच दशक तक जल संकट का पता नहीं चला। अब जनसंख्या बढ़ने से समस्या होने लगी है। दिल्ली में 2100 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी प्रति वर्ष उपलब्ध है। इसमें से 1600 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बह जाता है। साल में सात से आठ महीने वर्षा का पानी नहीं आता है। जिससे हम जलसंकट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ उपायों को अपनाकर इसे कम किया जा सकता है।

ऐसे निपट सकते हैं जलसंकट से: वर्षा जल संरक्षण करके और वेस्ट वाटर का दोबारा प्रयोग कर जल संकट से निपटा जा सकता है। वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर इसका प्रयोग पीने और खाना बनाने के स्थान पर दूसरी जरूरतों में किया जा सकता है। हालांकि सिंगापुर में तो एसटीपी का शोधित पानी पीने में भी प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अभी अपने यहां यह संभव नहीं है। लेकिन पार्कों की सिंचाई से लेकर टायलेट सफाई जैसे कामों में इसका उपयोग हो सकता है। इस पानी से हम 63 प्रतिशत मांग को पूरी कर सकते हैं। इसके लिए छोटे-छोटे एसटीपी प्लांट मोहल्लों में बनाने होंगे। वेस्ट वाटर का दोबारा इस्तेमाल करना ही 'नया पानी' है।

पार्कों में बनाने होंगे छोटे-छोटे जलाशय: अभी तक यही धारणा है कि वर्षा के पानी से भूजल को रिचार्ज किया जाए। लेकिन दिल्ली में जहां गगनचुंबी इमारतें बन रहीं हैं वहीं जमीन के अंदर भी निर्माण कार्य हो रहे हैं। इसलिए एक सीमा तक ही भूजल रिचार्ज कर सकते हैं। जरूरत है कि अंडरग्राउंड टैंक बनाकर वर्षा जल को सहेजा जाए। इसके साथ ही पार्कों में छोटे जलाशय बनाने होंगे, जिससे भूजल रिचार्ज भी होगा और पार्कों की खूबसूरती भी बढ़ेगी।